

छठी भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता

प्रलिस के लयि:

[पेट्रोलयिम नरियातक देशों का संगठन, OPEC+, नवीकरणीय ऊर्जा](#)

मेन्स के लयि:

भारत के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ, भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली पहल

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

भारत और [पेट्रोलयिम नरियातक देशों के संगठन \(Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC\)](#) के बीच ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च-स्तरीय बैठक 9 नवंबर, 2023 को [ऑस्ट्रेलिया के वयिना में OPEC के सचवालय में आयोजति की गई](#)।

- बैठक में [तेल और ऊर्जा बाजारों](#) के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई।

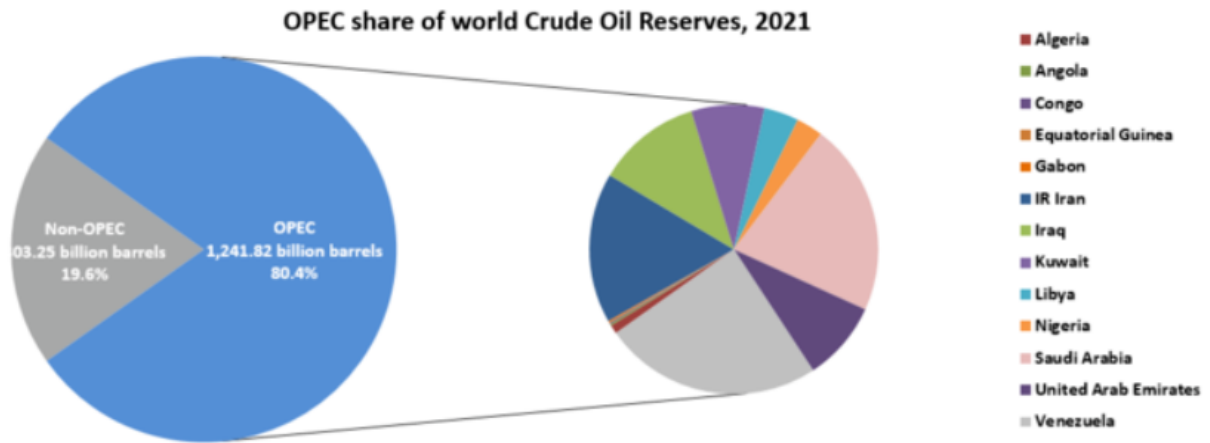
भारत-OPEC ऊर्जा वार्ता की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- बैठक में तेल और ऊर्जा बाजारों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रति कयिा गया, जसिमें [उपलब्धता, सामर्थ्य तथा स्थरिता](#) सुनशिचति करने पर वशिष जोर दयिा गया, जो कऊर्जा बाजारों की स्थरिता सुनशिचति करने के लयि आवश्यक हैं।
- बैठक दोनों पक्षों द्वारा [OPEC और भारत के बीच बढ़ते सहयोग](#) को बढ़ावा देने के महत्त्व को रेखांकति करने के साथ संपन्न हुई।
- [वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2023](#) का अनुमान है कभारत की [अर्थव्यवस्था वर्ष 2022-2045 के बीच 6.1 परतशित की औसत दीर्घकालिक वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख वकिसशील अर्थव्यवस्था होगी](#) और उसी दौरान [वृद्धशील वैश्विक ऊर्जा मांग 28 परतशित से अधिक होगी](#)।
 - दोनों पक्षों ने वैश्विक आर्थिक वकिस तथा ऊर्जा मांग में तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता, कच्चे तेल के आयातक एवं चौथे सबसे बड़े वैश्विक तेल शोधक के रूप में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार कयिा।
- बैठक में [नवीकरणीय ऊर्जा](#), ऊर्जा दक्षता, [हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था](#) तथा [जलवायु परिवर्तन](#) शमन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों एवं पहलों को भी स्वीकार कयिा गया।
- भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता के तहत अगली उच्च स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में भारत में आयोजति करने पर सहमतिबिनी।

पेट्रोलयिम नरियातक देशों का संगठन (OPEC) क्या है?

- **पारचिय:**
 - पेट्रोलयिम नरियातक देशों का संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC) एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जसिका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एवं वेनेजुएला द्वारा कयिा गया था।
 - इसका [मुख्यालय वयिना, ऑस्ट्रेलिया](#) में है।
- **उद्देश्य:**
 - OPEC का उद्देश्य [सदस्य देशों के बीच पेट्रोलयिम नीतियों का समनवय एवं एकीकरण करना](#) है, ताकपेट्रोलयिम उत्पादकों के लयि [उचित व स्थरि कीमतें](#) सुनशिचति की जा सकें; उपभोक्ता देशों को पेट्रोलयिम की आर्थिक रूप से उचित तथा नयिमति आपूर्ति की जा सके जससे संबद्ध उद्योग में नविश करने वालों को पूंजी पर उचित लाभ मल्लिगा।
- **सदस्य देश:**
 - अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गनि, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला इसके सदस्य हैं।

- OPEC के सदस्य देश वशिव के लगभग 30% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं।
 - संगठन के अंतर्गत सऊदी अरब सबसे बड़ा एकल तेल आपूर्तिकर्ता है , जो प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करता है।



OPEC proven crude oil reserves , at end 2021 (billion barrels, OPEC share)

Venezuela	303.47	24.4%	United Arab Emirates	111.00	8.9%	Algeria	12.20	1.0%	Equatorial Guinea	1.10	0.1%
Saudi Arabia	267.19	21.5%	Kuwait	101.50	8.2%	Angola	2.52	0.2%			
IR Iran	208.60	16.8%	Libya	48.36	3.9%	Gabon	2.00	0.2%			
Iraq	145.02	11.7%	Nigeria	37.05	3.0%	Congo	1.81	0.1%			

Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2022

//

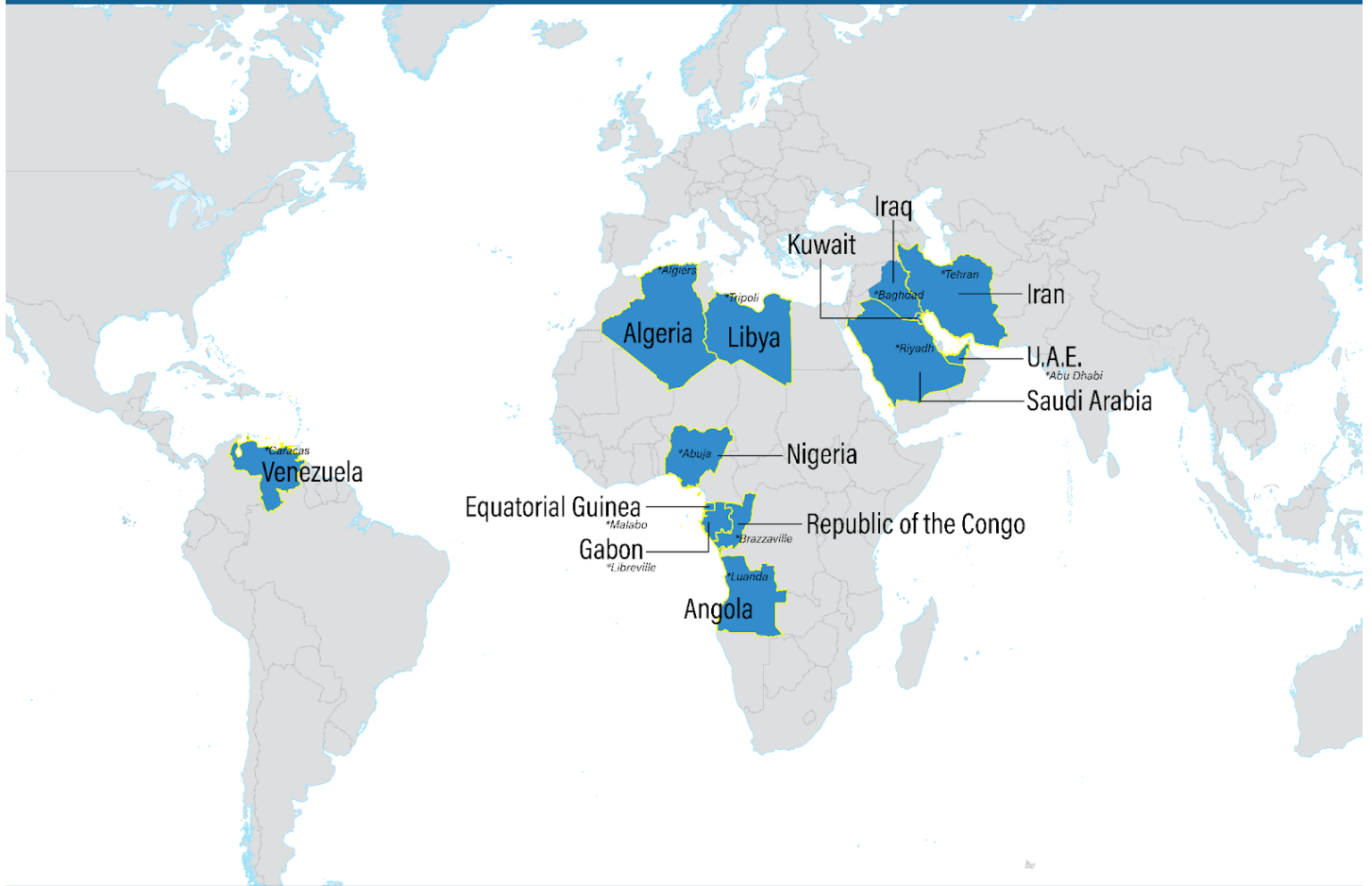
■ रपिर्ट और आउटलुक:

- मासिक तेल बाज़ार रपिर्ट, वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन और वशिव तेल आउटलुक।

■ ओपेक प्लस:

- वर्ष 2016 में अमेरिकी शेल तेल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप तेल की गरिती कीमतों के जवाब में ओपेक ने 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसे अब ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है।
 - ओपेक प्लस में अब अज़रबैजान, बहरीन, बरुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान के साथ 13 ओपेक सदस्य देश शामिल हैं।
- ओपेक प्लस देश संयुक्त रूप से वशिव के कुल कच्चे तेल का लगभग 40% का उत्पादन करते हैं।

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)



- Intergovernmental organisation, created at the Baghdad Conference (1960)
- Headquarter - Vienna, Austria
- Current Members - 13
- Members who Quit - Ecuador (2020), Qatar (2019), Indonesia (2016)
- Membership - Open to any country that is a substantial exporter of oil
- OPEC Fund for International Development - Only globally mandated development institution that provides financing from member to non-member countries exclusively.

सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. "वहनीय, वशिवसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये अनविर्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगतिपर टपिपणी कीजिये। (2018)

